जरुरी जानकारी | सरकार सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षण देगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केंद्र बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आदिवासी छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देगा।

एजेंसी न्यूज Bhasha | Mar 07, 2024 06:56 PM IST

नयी दिल्ली, सात मार्च केंद्र बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आदिवासी छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देगा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर दूरदराज के आदिवासी गांवों में मोबाइल और इंटरनेट संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पायलट आधार पर उपग्रह-आधारित तकनीक का उपयोग करने की भी योजना बना रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शुरू किया है। इसको देखते हुए आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर उद्योग में नौकरियों की काफी संभावनाएं हैं।

सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार इकाई है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और डिजाइन के क्षेत्र वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को तैयार करने के लिए एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले परिवेश का निर्माण करना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के साथ साझेदारी में, एक प्रशिक्षण फैब इकाई स्थापित करेगा। यह आदिवासी छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर एक पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

यह पाठ्यक्रम छात्रों के लिए उद्योग में उच्च-भुगतान वाली नौकरी का अवसर देगा।

भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक जी रंगराजन ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और संस्थान आदिवासी छात्रों को यथासंभव बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने यहां एक कार्यक्रम में पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि मंत्रालय उन्हें पीएम-जनमन योजना से जोड़ना चाहता है।

लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाला पीएम-जनमन, नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूह के लोगों के घरों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त करके सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

मंत्री ने कहा, "जब हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि जनजातीय समुदाय के लोग पीछे न रहें।"

मुंडा ने अधिकारियों से सुदूर आदिवासी इलाकों में मोबाइल 'कनेक्टिविटी' बेहतर बनाने पर भी ध्यान देने को कहा।

अधिकारियों ने कहा कि कई आदिवासी गांव भौगोलिक रूप से सुदूर क्षेत्र में हैं और वहां मोबाइल संपर्क बेहतर नहीं है। मंत्रालय, इसरो के साथ मिलकर ऐसे आदिवासी गांवों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट आधार पर उपग्रह-आधारित तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)